



Lakshya IAS

academy

17

Sep 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. सीसीपीए ने भ्रामक टिपिंग संकेतों और डार्क पैटर्न 1. प्रथाओं के लिए रैपिडो पर जुर्माना लगाया

सितंबर २०२६ में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक टिपिंग संकेतों और अनुचित इंटरफेस प्रथाओं के उपयोग के लिए ऑनलाइन एग्रीगेटर रैपिडो पर जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने कन्फर्म-शेमिंग और इंटरफेस हस्तक्षेप जैसी तकनीकों की पहचान की, जो उपभोक्ताओं को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रभावित कर सकती हैं, जिन्हें वे अन्यथा नहीं लेते। ऐसे भ्रामक या हेरफेर करने वाले उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइनों को आधिकारिक रूप से डार्क पैटर्न कहा जाता है। यह कार्रवाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं के सूचित और स्वैच्छिक निर्णय लेने को प्रभावित करने वाली डिजिटल प्रथाओं से उनकी सुरक्षा के लिए नियामकीय प्रयासों को दर्शाती है।



CCPA Fines Rapido for Misleading Tipping Prompts and Dark Pattern Practices

In September 2026, the Central Consumer Protection Authority penalized online aggregator Rapido for using misleading tipping prompts and unfair interface practices. The authority identified techniques such as confirm-shaming and interface interference, which could influence consumers into making decisions they might not otherwise take. Such deceptive or manipulative user interface designs are officially termed dark patterns. The action highlights regulatory efforts to protect consumers from digital practices that undermine informed and voluntary decision-making on online platforms.



मुख्य बिंदु:

- अग्रिम टिपिंग संकेत: सीसीपीए ने पाया कि यात्रा से पहले दिए जाने वाले टिपिंग संकेत उपभोक्ताओं पर सेवा प्राप्त करने से पहले अतिरिक्त भुगतान करने का दबाव डाल सकते हैं।
- डार्क पैटर्न संबंधी चिंताएं: इंटरफेस में कन्फर्म-शेमिंग और इंटरफेस हस्तक्षेप जैसी तकनीकों का उपयोग पाया गया, जो उपभोक्ताओं के स्वैच्छिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता था।
- उपभोक्ता संरक्षण कार्रवाई: प्राधिकरण ने जुर्माना लगाया और रैपिडो को अपने मंच से आपत्तिजनक टिपिंग संकेतों को बंद करने का निर्देश दिया।

Key Points:

- Advance tipping prompts: CCPA found that pre-ride tipping prompts could pressure consumers into paying extra before receiving the service.
- Dark pattern concerns: The interface was found to use confirm-shaming and interface interference techniques that could influence consumers' voluntary decisions.
- Consumer protection action: The authority imposed a penalty and directed Rapido to discontinue the objectionable tipping prompts from its platform.

2. सात राज्यों ने यमुना जल प्रबंधन में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

✍ २०२६ में, सात राज्यों ने यमुना जल के प्रबंधन में सहयोग मजबूत करने और लंबे समय से चले आ रहे अंतरराज्यीय जल-बंटवारे संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य उत्तरी भारत के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में विश्वसनीय पेयजल उपलब्धता में सुधार करना है। एक संबंधित परियोजना में हथिनीकुंड प्रणाली से भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से राजस्थान के आवंटित यमुना जल को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। यमुना गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और उत्तराखंड के हिमालय में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है।



मुख्य बिंदु:

- अंतरराज्यीय जल सहयोग: यह समझौता यमुना जल के प्रबंधन और लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय जल-बंटवारे संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए भाग लेने वाले राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करता है।
- पेयजल आपूर्ति: व्यापक यमुना व्यवस्थाओं का उद्देश्य उत्तरी भारत के कई जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में विश्वसनीय जल उपलब्धता में सुधार करना है।
- पाइपलाइन जल स्थानांतरण: एक संबंधित परियोजना में हथिनीकुंड प्रणाली से भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से राजस्थान के आवंटित यमुना जल को स्थानांतरित करने का प्रावधान है।

3. उपराष्ट्रपति ने भारत के वैश्विक जुड़ाव को मजबूत करने में आईसीडब्ल्यूए की भूमिका पर प्रकाश डाला

✍ सितंबर २०२६ में, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने भारत के वैश्विक जुड़ाव को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर सूचित चर्चाओं को बढ़ावा देने में भारतीय विश्व मामले परिषद की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के बढ़ते राजनयिक संपर्क और वैश्विक चुनौतियों के सामूहिक समाधान खोजने की उसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। आईसीडब्ल्यूए अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देता है और विदेश नीति संबंधी चर्चाओं में योगदान देता है। १९४८ में स्थापित यह संस्था नई दिल्ली स्थित सप्रू हाउस में मुख्यालय रखती है, जो अंतरराष्ट्रीय मामलों का एक ऐतिहासिक केंद्र है।



Seven States Sign Agreement to Strengthen Cooperation on Yamuna Water Management

✍ In 2026, seven states signed an agreement to strengthen cooperation in managing Yamuna waters and address long-standing interstate water-sharing concerns. The arrangements aim to improve reliable drinking water availability in water-stressed regions of northern India. A related project provides for transferring Rajasthan's allocated Yamuna water through underground pipelines from the Hathnikund system. The Yamuna is an important tributary of the Ganga and originates from the Yamunotri Glacier in Uttarakhand's Himalayas. =



Key Points:

- Interstate water cooperation: The agreement strengthens coordination among participating states for managing Yamuna waters and addressing long-standing regional water-sharing concerns.
- Drinking water supply: The broader Yamuna arrangements seek to improve reliable water availability for several water-stressed regions across northern India.
- Pipeline water transfer: A related project provides for transferring Rajasthan's allocated Yamuna water through underground pipelines from the Hathnikund system.

3. Vice President Highlights ICWA's Role in Strengthening India's Global Engagement

✍ In September 2026, Vice President C P Radhakrishnan highlighted the growing role of the Indian Council of World Affairs in strengthening India's global engagement and promoting informed discussions on international affairs. He emphasised India's expanding diplomatic outreach and its commitment to finding collective solutions to global challenges. The ICWA supports public understanding of international relations and contributes to foreign policy discussions. Established in 1943, the institution is headquartered at Sapru House in New Delhi, a historic centre for



मुख्य बिंदु:

- वैश्विक राजनयिक संपर्क: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने समकालीन अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करते हुए विभिन्न देशों और क्षेत्रों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव पर प्रकाश डाला।
- शांतिपरक विदेश नीति: उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक समस्याओं के लिए सामूहिक समाधान आवश्यक हैं और भारत को शांति के लिए एक बढ़ती प्रभावशाली आवाज बताया।
- आईसीडब्ल्यू की संस्थागत भूमिका: भारतीय विश्व मामले परिषद अंतरराष्ट्रीय मामलों की सार्वजनिक समझ में योगदान देती है और विदेश नीति पर सूचित चर्चा का समर्थन करती है।

4. केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम के खेल बुनियादी ढांचे की समीक्षा की और साईं आइजोल केंद्र का दौरा किया

- ✎ केंद्रीय मंत्री की मिजोरम यात्रा का केंद्र खेल बुनियादी ढांचे की समीक्षा करना और खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण अवसरों में सुधार की आवश्यकताओं का आकलन करना था। आइजोल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र में खिलाड़ियों की तैयारी, प्रशिक्षण और खेल विकास में सहायता करने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। मिजोरम को खेलो इंडिया रूपरेखा के तहत खेल सुविधाओं के विकास के लिए सहायता मिली है, जिसमें फुटबॉल बुनियादी ढांचा, बहुउद्देश्यीय सुविधाएं और हॉकी सुविधाएं शामिल हैं। आइजोल केंद्र में स्वीकृत परियोजना में प्रकाश व्यवस्था की स्थापना के साथ कृत्रिम हॉकी टर्फ बिछाना शामिल है, जिससे हॉकी प्रशिक्षण के लिए केंद्र की क्षमता मजबूत होगी।



मुख्य बिंदु:

- बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा: यात्रा के दौरान मिजोरम में खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण अवसरों में सुधार के उद्देश्य से खेल सुविधाओं और चल रही बुनियादी ढांचे संबंधी आवश्यकताओं का आकलन किया गया।
- साईं केंद्र का निरीक्षण: मंत्री ने आइजोल केंद्र में सुविधाओं की समीक्षा की और खिलाड़ियों की तैयारी, प्रशिक्षण तथा खेल विकास में सहायता करने वाली व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

international affairs.

Key Points:

- Global diplomatic outreach: Vice President C P Radhakrishnan highlighted India's expanding engagement with countries and regions while addressing contemporary international challenges.
- Peace-oriented foreign policy: He emphasised that global problems require collective solutions and described India as an increasingly influential voice for peace.
- ICWA institutional role: The Indian Council of World Affairs contributes to public understanding of international affairs and supports informed discussion on foreign policy.

Union Minister Reviews Mizoram's Sports Infrastructure and Visits SAI Aizawl Centre

- ✎ The Union Minister's visit to Mizoram focused on reviewing sports infrastructure and assessing the requirements for improving training opportunities for athletes. At the Sports Authority of India Training Centre in Aizawl, facilities supporting athlete preparation, coaching and sports development were inspected. Mizoram has received assistance under the Khelo India framework for developing sports facilities, including football infrastructure, multipurpose facilities and hockey facilities. At the Aizawl centre, the sanctioned project involves laying synthetic hockey turf along with installation of lighting, strengthening the centre's capacity for hockey training.



Key Points:

- Infrastructure development review: The visit assessed sports facilities and ongoing infrastructure requirements aimed at improving training opportunities for athletes across Mizoram.
- SAI centre inspection: The minister reviewed facilities at the Aizawl centre and examined arrangements supporting athlete preparation, coaching and sports development.

- खेलो इंडिया सहायता: मिजोरम को कृत्रिम हॉकी टर्फ, फुटबॉल बुनियादी ढांचे और बहुउद्देश्यीय खेल सुविधाओं सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए सहायता मिली है।

5. श्रेया योजना ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा सहायता का विस्तार किया

- ✎ केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा सहायता और वित्तीय सहायता को मजबूत करने के लिए अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए श्रेया छत्रक योजना का विस्तार किया। श्रेया का पूर्ण



रूप उच्च शिक्षा युवाओं के लिए प्रशिक्षुता और कौशल योजना है। श्रेया कई कल्याणकारी घटकों को एकीकृत करती है। इन घटकों में उत्कृष्ट शिक्षा छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और विदेश में अध्ययन के लिए ब्याज सब्सिडी शामिल हैं। १.४४ करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ-साथ बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए, यह पहल वित्तीय बाधाओं को दूर करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और भारत तथा विदेशों में शीर्ष स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए कार्य करती है।

मुख्य बिंदु:

- उच्च शिक्षा सहायता: श्रेया अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा, अनुसंधान, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में अध्ययन से संबंधित सहायता प्रदान करती है।
- छात्रवृत्ति कवरेज: छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से १.४४ करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ मिला है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी पर्याप्त सहायता मिलती है।
- बहुआयामी सहायता घटक: यह योजना पात्र छात्रों के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करने हेतु उत्कृष्ट शिक्षा, निःशुल्क कोचिंग, अध्येतावृत्ति और विदेश में छात्रवृत्ति के अवसरों को एक साथ जोड़ती है।

- Khelo India support: Mizoram has received assistance for facilities including synthetic hockey turf, football infrastructure and multipurpose sporting facilities.

5. SHREYAS Scheme Expands Higher Education Support for SC and OBC Students

- ✎ The central government expanded the reach of the SHREYAS umbrella scheme to strengthen higher education assistance and financial aid for Scheduled Castes, Other Backward Classes, and Economically Backward Classes. Short for Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills, SHREYAS integrates multiple welfare components. These components include top-class education scholarships, free coaching, national fellowships, and interest subsidies for overseas studies. Benefiting over one point forty-four crore SC students alongside substantial OBC and EBC beneficiaries, the initiative works to eliminate financial barriers, enhance employability, and facilitate access to top-tier academic institutions both across India and internationally.



Key Points:

- Higher education assistance: SHREYAS supports SC, OBC and EBC students through interventions covering higher education, research, competitive examinations and overseas studies.
- Scholarship coverage: More than 1.44 crore SC students have benefited from scholarship programmes, while OBC and EBC students also receive substantial assistance.
- Multiple support components: The scheme combines top-class education, free coaching, fellowships and overseas scholarship opportunities to reduce financial barriers for eligible students.

6. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मासिक बुलेटिन नवीनतम

श्रम बाजार संकेतक प्रस्तुत करता है

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अगस्त २०२६ के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मासिक बुलेटिन जारी किया



है, जिसमें देशभर के श्रम बाजार में लगातार सुधार को उजागर किया गया है। जुलाई में दर्ज सकारात्मक रुझानों के बाद, १५ वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र बेरोजगारी दर घटकर ५.० प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही, कार्यबल में भागीदारी में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। समग्र श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर ५५.६ प्रतिशत हो गई और श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर ५२.८ प्रतिशत हो गया, जो मार्च के बाद का उच्चतम स्तर है। महिला रोजगार में भी वृद्धि जारी रही, जिसमें महिला भागीदारी *४.८ प्रतिशत तक पहुंच गई। रोजगार संकेतकों में यह मजबूती मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रेरित रही, जहां कार्यबल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि और बेरोजगारी में कमी देखी गई।

मुख्य बिंदु:

- श्रम भागीदारी में सुधार: जुलाई २०२६ के बुलेटिन में १५ वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र श्रम बल भागीदारी दर ५५.४ प्रतिशत दर्ज की गई।
- बेरोजगारी दर में गिरावट: जुलाई के दौरान समग्र बेरोजगारी दर जून के ५.५ प्रतिशत से घटकर ५.१ प्रतिशत हो गई, जो श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार को दर्शाती है।
- महिला भागीदारी में वृद्धि: जुलाई २०२६ के दौरान महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर *४.४ प्रतिशत हो गई, जबकि समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर ५२.५ प्रतिशत हो गया।

6. PLFS Monthly Bulletin Presents Latest Labour Market Indicators

The National Statistical Office has released the Periodic Labour Force Survey Monthly Bulletin for August 2026, highlighting continuous improvements across the nationwide labour market. Following positive trends recorded earlier in July, the overall unemployment rate for individuals aged 15 years and above declined to 5.0 percent. Simultaneously, workforce engagement expanded significantly. The overall Labour Force Participation Rate rose to 55.6 percent, and the Worker Population Ratio increased to 52.8 percent, reaching its highest level since March. Female employment also continued its upward trajectory, with female participation reaching 34.8 percent. These strengthening employment indicators were predominantly driven by rural areas, which witnessed notable workforce participation growth and decreasing joblessness.



Key Points:

- Labour participation improves: The July 2026 bulletin recorded overall LFPR at 55.4 percent for persons aged 15 years and above.
- Unemployment rate declines: Overall unemployment declined to 5.1 percent from 5.5 percent in June, indicating improved labour-market conditions during July.
- Female participation rises: Female LFPR increased to 34.4 percent, while overall WPR rose to 52.5 percent during July 2026.

7. विश्व परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच २०२६ सतत संसाधन उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए गांधीनगर में शुरू हुआ

विश्व परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच २०२६ गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हुआ, जो पहली बार दक्षिण एशिया में इस वैश्विक पर्यावरण मंच की मेजबानी का अवसर है। लोगों और समृद्धि के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था परिवर्तन विषय के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में ६५ से अधिक देशों के २,००० से अधिक विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक शामिल हुए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त रूप से मंच का उद्घाटन किया। मंच का ध्यान परिपत्र वित्त को बढ़ावा देने, साझेदारी मजबूत करने और सतत संसाधन प्रबंधन के लिए डिजिटल समाधानों को आगे बढ़ाने पर है। १२५ से अधिक प्रदर्शकों वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में अपशिष्ट को कम करने और मूल्यवान संसाधनों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनः शामिल करने के लिए व्यावहारिक नवाचार प्रदर्शित किए गए।



World Circular Economy Forum 2026 Opens in Gandhinagar with Focus on Sustainable Resource Use

The World Circular Economy Forum 2026 opened at Mahatma Mandir in Gandhinagar, marking the first time South Asia hosted this global environmental platform. Organised under the theme Circular Economy Transition for People and Prosperity, the event brought together over two thousand cross-sectoral stakeholders from more than sixty-five countries. Jointly inaugurated by Union Environment Minister Bhupender Yadav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, the forum focuses on mobilising circular finance, strengthening partnerships, and advancing digital solutions for sustainable resource management. An international exposition showcasing over one hundred twenty-five exhibitors highlighted practical innovations designed to minimize waste and loop valuable resources back into the global economy.



मुख्य बिंदु:

- वैश्विक परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच: विश्व परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच २०२६ का आयोजन १५ से १८ सितंबर तक गांधीनगर में स्थिरता-केंद्रित विषय के तहत किया जा रहा है।
- अंतरराष्ट्रीय भागीदारी: ६५ से अधिक देशों के २,००० से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें सरकारों, व्यवसायों और अन्य संगठनों को एक साथ लाया गया है।
- परिपत्र समाधानों का प्रदर्शन: मंच में १२५ से अधिक प्रदर्शकों वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी शामिल है, जिसमें परिपत्रता और संसाधन दक्षता पर केंद्रित समाधान प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

Key Points:

- Global circular economy forum: The World Circular Economy Forum 2026 is being held in Gandhinagar from September 15 to 18 under a sustainability-focused theme.
- International participation: More than 2,000 stakeholders from over 65 countries are participating, bringing together governments, businesses and other organisations.
- Circular solutions showcase: The forum includes an international exposition featuring more than 125 exhibitors presenting solutions focused on circularity and resource efficiency.

8. १२वां जिला कलेक्टर पेयजल संवाद पेयजल वितरण को मजबूत करने पर केंद्रित

✎ जल शक्ति मंत्रालय ने १२वें जिला कलेक्टर पेयजल संवाद का आयोजन किया, जिसमें जल जीवन मिशन २.० के तहत ग्रामीण पेयजल सेवा वितरण में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासकों को एक साथ लाया गया। यह राष्ट्रीय संवाद केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर ग्रामीण परिवारों को दीर्घकालिक और सतत जल सेवा उपलब्ध कराने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। जिला नेतृत्व ने सुरक्षित और नियमित नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहकर्म-शिक्षण मॉडल, डिजिटल परिसंपत्ति निगरानी और जल स्रोत स्थिरता पहलों की समीक्षा की। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके, शिकायत निवारण को मजबूत करके और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देकर, यह संवाद स्थानीय शासन निकायों को जलवायु-अनुकूल और विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने में सक्षम बनाता है, जो दीर्घकालिक परिचालन दक्षता सुनिश्चित करती हैं।



मुख्य बिंदु:

- जिला स्तर पर समन्वय: पेयजल संवाद ग्रामीण पेयजल सेवा वितरण में तेजी लाने और उसे मजबूत करने के लिए जिला प्रशासकों को एक साथ लाता है।
- जल जीवन मिशन: चर्चाओं में बेहतर निगरानी, समन्वय और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल जीवन मिशन २.० के कार्यान्वयन में सुधार पर ध्यान दिया गया।
- सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान: यह पहल जिलों को जल स्रोत स्थिरता, सेवा वितरण, शिकायत निवारण और व्यवहार परिवर्तन से संबंधित व्यावहारिक दृष्टिकोण साझा करने में सक्षम बनाती है।

8. 12th District Collectors' Peyjal Samvad Focuses on Strengthening Drinking Water Delivery

✎ The Ministry of Jal Shakti convened the twelfth District Collectors' Peyjal Samvad, bringing together district administrators to accelerate rural drinking water service delivery under Jal Jeevan Mission two point zero. The national dialogue marks a major strategic shift in focus from mere infrastructure creation to long-term sustainable water service delivery across rural households. District leadership reviewed peer-learning models, digital asset tracking, and source sustainability initiatives to ensure safe, regular tap water supply. By encouraging community participation, strengthening grievance redressal, and fostering inter-agency coordination, the interactive forum empowers local governance bodies to build climate-resilient, decentralized water management systems that guarantee long-term operational efficiency.



Key Points:

- District-level coordination: The Peyjal Samvad brings district administrators together to accelerate implementation and strengthen rural drinking water service delivery.
- Jal Jeevan Mission: Discussions focus on improving implementation of Jal Jeevan Mission 2.0 through stronger monitoring, coordination and community participation.
- Best practices sharing: The initiative enables districts to exchange practical approaches concerning source sustainability, service delivery, grievance resolution and behavioural change.

9. कोल इंडिया ने प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव के माध्यम से स्मार्ट खनन को आगे बढ़ाया

राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी खनन गतिविधियों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और



ड्रोन निगरानी को एकीकृत करके अपने डिजिटल बदलाव को तेज किया है। अपनी स्मार्ट खनन पहल के तहत, कंपनी पारंपरिक तरीकों से डेटा आधारित खुली खदान और भूमिगत परिचालन की ओर बढ़ने के लिए इन उन्नत प्रौद्योगिकियों को लागू कर रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों का उपयोग ऑपरेटर की थकान की निगरानी, निकटता चेतावनी और स्वचालित सुरक्षा प्रणालियों के लिए किया जा रहा है, जबकि ड्रोन, लिडार और भौगोलिक सूचना प्रणाली मंच भू-स्थानिक सर्वेक्षण और पर्यावरणीय लेखा-परीक्षण को बेहतर बनाते हैं। वैश्विक स्थिति प्रणाली आधारित बेड़े की निगरानी और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण से समर्थित यह डिजिटल बदलाव उत्पादकता बढ़ाता है, संसाधन पुनर्प्राप्ति को बेहतर करता है और देशभर की सुविधाओं में कार्यस्थल के खतरों को कम करता है।

मुख्य बिंदु:

- डिजिटल खनन प्रणालियां: कोल इंडिया खनन दक्षता और परिचालन निगरानी में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों, एकीकृत कमान प्रणालियों और डेटा आधारित उपकरणों को अपना रही है।
- उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना: पहलों में 5जी संपर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनुप्रयोग, पूर्वानुमानात्मक रखरखाव, स्वचालित मशीनरी और वास्तविक समय परिचालन निगरानी शामिल हैं।
- सुरक्षा और उत्पादकता: प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों का उद्देश्य कार्यस्थल की सुरक्षा को मजबूत करना, निर्णय लेने में सुधार करना और खनन परिचालन में उत्पादकता बढ़ाना है।

Coal India Advances Smart Mining Through Technology-Driven Transformation

State-owned public sector enterprise Coal India Limited has accelerated its digital transformation by



integrating Internet of Things, Artificial Intelligence, and Drone Surveillance into its mining operations. Under its Smart Mining initiative, the company is deploying these advanced technologies to transition from conventional methods to data-driven open-cast and underground operations. AI-based tools are being utilized for operator fatigue monitoring, proximity warnings, and automated safety systems, while drones, LiDAR, and GIS platforms enhance geospatial surveying and environmental auditing. Supported by GPS fleet tracking and predictive analytics, this digital shift boosts productivity, optimizes resource recovery, and minimizes workplace hazards across facilities nationwide.

Key Points:

- Digital mining systems: Coal India is adopting digital technologies, integrated command systems and data-driven tools to improve mining efficiency and operational oversight.
- Advanced technology adoption: Initiatives include 5G connectivity, Internet of Things applications, predictive maintenance, automated machinery and real-time operational monitoring.
- Safety and productivity: Technology-enabled systems are intended to strengthen workplace safety, improve decision-making and enhance productivity across mining operations.

10. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध अभ्यास २०२६ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया

भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने अपने वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध अभ्यास २०२६ के २२वें संस्करण की शुरुआत की। राजस्थान के बीकानेर



और उत्तराखंड के औली में ऐतिहासिक दो-क्षेत्रीय प्रारूप में आयोजित यह अभ्यास रेगिस्तानी युद्धाभ्यास, लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध पर केंद्रित है। एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के रूप में, अभ्यास में पहली बार मोबाइल ड्रोन-रोधी प्रणालियों को तैनात किया गया, विशेष रूप से मोबाइल लो, स्लो, स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इंटीग्रेटेड डिफेंड सिस्टम। यह उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी बलों को जटिल परिस्थितियों में शत्रु सामरिक ड्रोन का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम बनाती है। अमेरिकी आर्कटिक प्रशिक्षित सैनिकों और बहु-क्षेत्रीय कार्यबलों की भागीदारी से यह अभ्यास विभिन्न क्षेत्रों में सामरिक सहयोग, कमान और नियंत्रण एकीकरण तथा युद्धक्षेत्र की तैयारी को मजबूत करता है।

मुख्य बिंदु:

- २२वां संस्करण: युद्ध अभ्यास २०२६ भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का २२वां संस्करण है।
- एकाधिक प्रशिक्षण स्थान: यह अभ्यास ९ से २८ सितंबर तक राजस्थान के बीकानेर और उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है।
- उन्नत युद्ध क्षमताएं: अभ्यास में परिचालन अंतरसंचालनीयता को मजबूत करने के लिए उन्नत कमान और नियंत्रण तथा लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमताओं के साथ ड्रोन-रोधी प्रणालियों को शामिल किया गया है।

10. India and the United States Begin Yuddh Abhyas 2026 Joint Military Exercise

The Indian Army and the United States Army commenced the twenty-second edition of their annual bilateral military training, Exercise Yuddh



Abhyas two thousand twenty-six. Held in a historic two-theatre format across Bikaner in Rajasthan and Auli in Uttarakhand, the drill focuses on desert maneuvers, long-range precision fires, and high-altitude warfare. Marking a critical technical milestone, the exercise saw the first-ever deployment of mobile counter-drone systems, specifically the Mobile Low, Slow, Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System. This advanced defense technology allows forces to detect, track, and neutralize hostile tactical drones in complex environments. Featuring US Arctic-trained troops and multi-domain task forces, the exercise enhances cross-domain tactical cooperation, command-and-control integration, and battlefield readiness.

Key Points:

- Twenty-second edition: Yuddh Abhyas 2026 is the 22nd iteration of the annual bilateral military exercise between the Indian and United States armies.
- Multiple training locations: The exercise is being conducted from September 9 to 28 at Bikaner in Rajasthan and Auli in Uttarakhand.
- Advanced combat capabilities: The exercise introduces counter-drone systems alongside advanced command-and-control and long-range precision capabilities to strengthen operational interoperability.



दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. युद्ध अभ्यास २०२६ के संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान पहली बार किस अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी को एकीकृत और तैनात किया गया ?

- (a) हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन
- (b) मोबाइल ड्रोन-रोधी प्रणालियां
- (c) निर्देशित ऊर्जा लेजर तोपें
- (d) स्वायत्त जलमग्न वाहन

Q2. राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड ने २०२६ में अपनी 'स्मार्ट खनन' पहल के तहत खुली खदान परिचालनों में डिजिटल बदलाव को तेज करते हुए किन प्रमुख प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया ?

- (a) इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन निगरानी
- (b) क्वांटम एन्क्रिप्शन और ब्लॉकचेन
- (c) परमाणु ऊर्जा चालित उत्खनन ड्रिलिंग
- (d) त्रिआयामी जैव मुद्रण प्रणालियां

Q3. जल जीवन मिशन २.० के तहत हाल ही में बदलते जिला कलेक्टर पेयजल संवाद के मुख्य फोकस को निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सबसे अच्छी तरह दर्शाता है ?

- (a) ग्रामीण स्वच्छता से शहरी बुनियादी ढांचे की ओर
- (b) बुनियादी ढांचे के निर्माण से सतत जल सेवा वितरण की ओर
- (c) भूजल प्रबंधन से नदी जोड़ने की ओर
- (d) घरेलू नल कनेक्शन से सिंचाई कवरेज की ओर

Q4. गुजरात में आयोजित विश्व परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच २०२६ का आधिकारिक विषय क्या था ?

- (a) हरित ग्रह के लिए शून्य अपशिष्ट
- (b) अगली पीढ़ी के उद्योग के लिए पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियां
- (c) विकासशील देशों में सतत संसाधन उपयोग
- (d) लोगों और समृद्धि के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था: परिवर्तन

Q5. अगस्त २०२६ में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मासिक बुलेटिन के अनुसार, १५ वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की समग्र बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई ?

- (a) ६.२ प्रतिशत
- (b) ५.८ प्रतिशत
- (c) ५.० प्रतिशत
- (d) ४.१ प्रतिशत

Q1. What cutting-edge defense technology was integrated and deployed for the very first time during the Yudh Abhyas 2026 joint military drills?

- (a) Hypersonic Glide Vehicles
- (b) Mobile Counter-Drone Systems
- (c) Directed Energy Laser Cannons
- (d) Autonomous Submersible Vehicles

Q2. State-owned PSU Coal India Limited (CIL) accelerated its digital shift in 2026 by integrating which key technologies into its open-cast mining operations under its 'Smart Mining' initiative?

- (a) Internet of Things (IoT), AI, and Drone Surveillance
- (b) Quantum Encryption and Blockchain
- (c) Nuclear-powered Excavation Drilling
- (d) 3D Bioprinting Systems

Q3. Which of the following best describes the recently changing focus of the District Collectors' Peyjal Samvad under Jal Jeevan Mission 2.0?

- (a) From rural sanitation to urban infrastructure
- (b) From infrastructure creation to sustainable water service delivery
- (c) From groundwater management to river linking
- (d) From household tap connections to irrigation coverage

Q4. What was the official theme for the World Circular Economy Forum (WCEF) 2026 held in Gujarat?

- (a) Zero Waste for a Green Planet
- (b) Recycling Technologies for Next-Gen Industry
- (c) Sustainable Resource Use in Developing Nations
- (d) Circular Economy: Transition for People and Prosperity

Q5. According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) Monthly Bulletin released for August 2026, India's overall Unemployment Rate (UR) for individuals aged 15 years and above declined to what percentage?

- (a) 6.2 percent
- (b) 5.8 percent
- (c) 5.0 percent
- (d) 4.1 percent

Q6. केंद्र सरकार ने २०२६ में उत्कृष्ट उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए श्रेया छत्रक योजना के दायरे का विस्तार किया। 'श्रेया' का पूर्णरूप क्या है?

- (a) उच्च शिक्षा युवाओं के लिए प्रशिक्षुता और कौशल योजना
- (b) युवाओं और छात्रों के लिए उच्च शिक्षा सहायता योजना
- (c) युवाओं और विद्वानों के लिए सामाजिक उच्च संसाधन और सशक्तिकरण
- (d) उच्च शैक्षिक संसाधन और युवा सहायता प्रणाली

Q7. मिजोरम में खेल बुनियादी ढांचे की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आइजोल स्थित साई प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। खेलो इंडिया रूपरेखा के तहत केंद्र के लिए कौन-सी बुनियादी ढांचा परियोजना स्वीकृत की गई है?

- (a) कृत्रिम फुटबॉल मैदान का निर्माण
- (b) नए एथलेटिक्स स्टेडियम का विकास
- (c) इनडोर तैराकी परिसर का निर्माण
- (d) कृत्रिम हॉकी टर्फ बिछाना और प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना

Q8. सितंबर २०२६ में भारत की राजनयिक कूटनीति और वैश्विक संपर्क को बढ़ाने के लिए चर्चा में रही भारतीय विश्व मामले परिषद (आईसीडब्ल्यूए) का मुख्यालय किस ऐतिहासिक भवन में स्थित है?

- (a) हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली
- (b) विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- (c) जवाहर भवन, नई दिल्ली
- (d) सप्रू हाउस, नई दिल्ली

Q9. यमुना नदी, जिसने हाल ही में २०२६ में एक प्रमुख बहु-राज्यीय प्रबंधन समझौता देखा, हिमालय के निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है?

- (a) गंगोत्री हिमनद
- (b) यमुनोत्री हिमनद
- (c) सियाचिन हिमनद
- (d) जेमू हिमनद

Q10. सितंबर २०२६ में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइनों और अनुचित प्रथाओं के उपयोग के लिए ऑनलाइन एग्रीगेटर रैपिडो पर जुर्माना लगाया। ऐसे उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइनों के लिए नियामक निकायों द्वारा आधिकारिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं या अनजाने में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं?

- (a) छाया रणनीतियां
- (b) डार्क पैटर्न
- (c) प्रेत इंटरफेस
- (d) गुप्त संकेत

Q6. The central government in 2026 expanded the scope of the SHREYAS umbrella scheme to provide top-class higher education scholarships. What does the acronym 'SHREYAS' stand for?

- (a) Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills
- (b) Scheme for Higher Education Support for Youth and Students
- (c) Social Higher Resources and Empowerment for Youth and Scholars
- (d) System for Higher Educational Resourcing and Youth Support

Q7. During the review of sports infrastructure in Mizoram, the Union Minister visited the SAI Training Centre in Aizawl. Which infrastructure project has been sanctioned for the centre under the Khelo India framework?

- (a) Construction of a synthetic football ground
- (b) Development of a new athletics stadium
- (c) Construction of an indoor swimming complex
- (d) Laying of synthetic hockey turf and installation of lighting

Q8. The Indian Council of World Affairs (ICWA), highlighted in September 2026 for enhancing India's diplomatic diplomacy and global outreach, is headquartered in which historical building?

- (a) Hyderabad House, New Delhi
- (b) Vigyan Bhawan, New Delhi
- (c) Jawahar Bhawan, New Delhi
- (d) Sapru House, New Delhi

Q9. The Yamuna River, which recently saw a major multi-state management agreement in 2026, originates from which of the following glaciers in the Himalayas?

- (a) Gangotri Glacier
- (b) Yamunotri Glacier
- (c) Siachen Glacier
- (d) Zemu Glacier

Q10. In September 2026, the Central Consumer Protection Authority (CCPA) penalized online aggregator Rapido for using deceptive UI designs and unfair practices. What is the official term used by regulatory bodies for such user interface designs that deceive or trick consumers into taking unintentional actions?

- (a) Shadow Tactics
- (b) Dark Patterns
- (c) Phantom Interfaces
- (d) Stealth Prompts

उत्तरमाला (Answer Key)

1 B

2 A

3 B

4 D

5 C

6 A

7 D

8 D

9 B

10 B

